

## EDITORIAL

# Tower Corporation- Dismantling Our Aerial Assets

In the name of Project Unnati KPMG consultant was appointed two years back to specify the augmentation of tower business with suitable organizational structure as in the lines of private operators. A meeting with KPMG people was arranged for all unions to know their recommendations. All the unions participated and in one voice opposed the recommendations and agreed to improve tenancy ratio by enhancing the sharing of number of towers. The following are some of the prime observations and recommendations of KPMG.

“Potential scenario: Market opportunity for 26-28,000 tenancies over FY14-FY18

Higher tenancy ratio with right pricing and focus on sales

**Efficient operations with high site uptime:** Separate financial and performance indicators

**Subsidiarisation Structure :** It is proposed that all tower business related assets, liabilities and operations be transferred to a subsidiary owned by BSNL

Because BSNL (a PSU) will hold majority stake in the subsidiary, the subsidiary will also be a PSU, and will follow all rules and guidelines applicable for PSUs

**Advantages :** Growth of tower business will not be affected by shortage of funds in BSNL. Tower business expansion will not burden BSNL's cashflows

BSNL pays an unnecessary license fee of 8% on the external revenues of towers business as well No license fee to be paid by the Tower Subsidiary BSNL saves the unnecessary outgo of license fee on the external revenues of towers business

Creation of SBU and Stabilization of business

Creation of subsidiary ■ Identification of assets to be transferred to (shared with)

the Subsidiary

Registration of the Tower Subsidiary

Transfer of all assets, liabilities and contracts to the new company

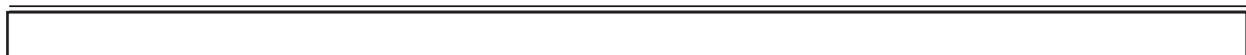
Hiring of personnel, if required

Establishment of mechanism for billing with BSNL

Creation of organization structure and transfer / deputation of personnel for Induct Strategic Partner: Because BSNL (a PSU) will hold majority stake in the JV, the business will be governed by rules and guidelines applicable for PSUs Impact of restructuring on employees: No down-sizing of BSNL employees.

No change in salary structure for employees. For employees transferred / deputed to Tower JV, same PSU guidelines for salary and retirements will be applicable. More employees may be hired to handle specific functions in the Tower JV”

During the same time CMD BSNL has informed the unions that the company is in an urgent need to revenues to meet capital expenditure and to modernize its existing assets in addition to meeting huge and disproportionate employees cost. To address the situation to some extent other revenue streams have got to be tapped using assets of the company. A proposal is under consideration to create subsidiary tower company to improve substantially the operations of our passive infra thereby generate additional revenue. But the findings of all the unions are having different facts and we opposed the proposal and cleared that it is nothing but striping out of BSNL's core networks and creating way forward for its privatization.



We come to know by Aug 6<sup>th</sup> 2015 thro press coverage that the Cabinet gave 'in-principle' approval for hiving off state-run Bharat Sanchar Nigam Ltd's (BSNL) tower assets into a separate company, aiming to generate additional stream of revenues for the loss-making unit. The department of telecommunications (DOT) has been asked to constitute an inter-ministerial group consisting of representatives from public enterprises, department of pension and pensioners' welfare and department of economic affairs for working out the capital structure and organisational structure of the new company, sources said. In turn DOT addressed the concern authorities to nominate joint secretary rank officers for the IMG.

On knowing this, NFTE BSNL had reacted sharply and addressed DOT for the non inclusion of the major stake holder BSNL's representatives even in the IMG. We were told that representative of BSNL was included. No Union was updated including the recognized unions about the development. We were also not given any copy of the BSNL note given to IMG or the decisions of IMG for preparing Cabinet note by DOT.

We come to know that the Govt is in hurry and preparing for cabinet approval to form and register separate tower company. We have our own misgivings that it is the surest way for bringing some corporate giant as strategic partner and subsequently handover the BSNL's hard earned thousands of crores of assets that private giant.

There are hell a lot of questions that need some healthy discussion and arrival at some understanding before the mad push of any subsidiary PSU for our towers.

a. What is the guarantee that the new subsidiary company would be a Govt company having 100% share of BSNL?

b. What will be the long run impact on BSNL financials due to the loosing of Aerial assets?

C. What are the guarantees for the employees sending on deputation? No employee will be sent without knowing the proper service conditions till agreement with the concerned Unions/Associations? Implications of BSNL Pay, 37A etc?

d. Is there any guarantee to opt back to the parent company if any apprehension of future of the tower company?

On further discussion amongst the unions and the management few more Questions may arise. In this uncertain situation, our National Forum has decided to voice our protest thro demonstration on Oct 27<sup>th</sup>. The other forum also synchronized its programme on the same day. Let us fight unitedly to safeguard the interests of BSNL financials as well as interests of our employees.



## टावर कार्पोरेशन – बाह्य संसाधनों का विनाश

दो वर्ष पहले उन्नति परियोजना के नाम पर के.पी.एम.जी कम्पनी को सलाह देने के लिए नियुक्ति दी गई थी। उस कम्पनी को विशेषतः टॉवर बिजनेस के लिए निजी कम्पनियों के अनुरूप संगठनात्मक स्वरूप बताने को कहा गया था। के.पी.एम.जी के साथ सभी श्रमिक संघों की बैठक भी बीएसएनएल ने करायी। सभी संघों ने एकस्वर एवं एकतम होकर के.पी.एम.जी. के अनुशांसा को अस्वीकार कर दिया तथा टावरों की उन्नत करके अधिक से अधिक हिस्सेदारी देकर राजस्व बढ़ाने की बात से सहमत हुए थे। के.पी.एम.जी. की कुछ अनुशांसाएं निम्न प्रकार हैं।

वर्ष 2014 से 2018 तक 26000-28000की काश्तकारी की व्यापारिक संभावना।

उच्च काश्तकारी को उचित मूल्य एवं बिक्री पर दबाव के अनुपातिक प्राप्ति सम्भव: दक्षता के साथ संचालन एवं उच्चतर अपटाइम संभावित

अलग परफॉर्मेंस एवं वित्तीय सूचक उपाधिकार-आकार – यह प्रस्तावित है कि टावर व्यापार से सम्बंधित सभी उपकरण, स्थानांतरित किया जायेगा।

क्योंकि बीएसएनएल सहायक टावर कम्पनी की अधिकतम हिस्सा रखेगी फिर भी टावर कम्पनी एक अलग लोक उपक्रम के हर दायित्व का वाहक होगा।

के.पी.एम.जी.के अनुशांसा के अनुसार टावर के विकास वित्तीय अभाव में अवरूद्ध नहीं होगा। टावर व्यापार के उत्थान में बीएसएनएल का अर्थाभाव वाधक नहीं होगा। बीएसएनएल अनावश्यक टावरों के लिए लाइसेंस शुल्क दे रही है। अलग कम्पनी बनने से लाइसेंस शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये सभी बातें केवल आम जन एवं कर्मचारियों को गुमराह करने के लिए कही गई है। वास्तविकता यह है कि बीएसएनएल को भी उक्त कम्पनी को किराया देना होगा टावरों के इस्तेमाल के लिए। जब टावर कम्पनी को बड़े आधार पर टावर की संरचना स्थापित करनी होगी तो धनाभाव के नाम पर निजी क्षेत्र के लिए दरवाजा खोल दिया जायेगा और सहायक टावर कम्पनी निजी क्षेत्र के हाथ में चली जायेगी।

उसी समय सी.एम.डी. सभी श्रमिक संघों को सूचना दी कि कम्पनी की विकास एवं भारी कर्मचारी संख्या पर होने

वाले खर्च के मुकाबला के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति का श्रोत दूदना होगा और इस सम्बंध में सहायक टावर कम्पनी हमारी हित रक्षा कर सकती है, हमें बिना खर्च किये इस कम्पनी से राजस्व की प्राप्ति होगी परन्तु श्रमिक संघों ने वास्तविक स्थिति को भांपते हुए इसका विरोध किया क्योंकि यह महसूस किया गया कि यह बीएसएनएल को निजी हाथों में देने का परोक्ष तरीका है।

विगत 6 अगस्त 2015 को समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि संघीय मंत्री परिषद ने बीएसएनएल के टावरों के लिए एक अलग कम्पनी बनाकर अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति करने, जो आर्थिक रूप से पिछड़ते हुए बीएसएनएल के हित में होगी। कैबिनेट ने सिद्धान्त रूप में सहायक कम्पनी बनाने की पुष्टि कर दी।

दूरसंचार विभाग को निदेशित किया गया कि अन्तर मंत्रालय समिति जिनमें लोक उपक्रम विभाग, पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग तथा आर्थिक मामले के विभाग से अधिकारियों का एक समिति गठित कर नयी कम्पनी के लिए आधारभूत संरचना एवं संगठनात्मक पहलू पर अध्ययन करे विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। इस समिति में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को नामित करने को कहा गया। विशेष आश्चर्य की बात तब हुई जब पता चला कि बीएसएनएल कम्पनी को तोड़कर अलग कम्पनी बनानी है, उस संगठन से कोई अधिकारी उस समिति नहीं लिया गया। एनएफटीई ने इस निर्णय का विरोध किया तथा बाद में पता चला कि बीएसएनएल से भी अधिकारी उक्त समिति में शामिल किये गये हैं।

समिति के गठन के उपरान्त एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी यूनियन को वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं दी गई। हमें बीएसएनएल द्वारा तैयार की गई नोट की प्रति भी नहीं दी गई।

अभी हमें ज्ञात हुआ है कि सरकार बहुत जल्दबाजी में कैबिनेट से इस कम्पनी की स्थापना का अनुमोदन कराकर इसकी स्थापना शीघ्र सुनिश्चित करना चाहती है और हम यह ठोस रूप से जानते हैं कि इसके पीछे बीएसएनएल में कार्पोरेट दैत्यों को स्टैटजिक पार्टनर बनाकर प्रवेश कराना है



और अन्ततः इस विशालकाय बीएसएनएल को निजी हाथों में धकेल देना है।

सरकार के इस कदम से कर्मचारियों के मन में बहुत प्रश्न कौंध रहे हैं। यथा क्या गारंटी है कि बनने वाली कम्पनी की शत प्रतिशत हिस्सा पूंजी बीएसएनएल की होगी। टावर को खोकर बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति क्या होगी? कर्मचारियों के साथ क्या होगा। आदि अनेक प्रश्न हैं जो कर्मचारियों को उद्धेलित कर रहे हैं।

नेशनल फोरम ऑफ बीएसएनएल वर्कर्स ने 27 अक्टूबर 2016 को प्रदर्शन के माध्यम से विरोध दर्ज करा रही हैं अन्य फोरम भी उसी तिथि को प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी पक्ष का सम्पूर्ण विरोध इस मामले में रेखांकित करती है कि सरकार को पुनर्विचार करते हुए इस कम्पनी के गठन की बात बंद करनी चाहिए।

